>

Title: Need to give environmental clearance to construct iron gate of Kutku dam, part of the inter-state North Koel Irrigation Project, in Latehar district, Jharkhand.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना का कार्यारम्भ 1975 में हुआ। इसकी प्रारम्भिक लागत मात्र 30 करोड़ रुपए थी, जिस पर अभी तक लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है लेकिन 35 वर्षों तक कार्य पूरा नहीं होने के कारण अब इसकी अनुमानित लागत 1600 करोड़ रुपए हैं। स्थापना व्यय प्रति वर्ष आवर्तक खर्च के रूप में लगभग 10 करोड़ है। इस योजना से बिहार के औरंगाबाद, गया और झारखंड के पलामू जिले की एक लाख चौबीस हजार हेक्टेयर (124000 हेक्टेयर) जमीन में सिंचाई होगी तथा डैम से 24 मेगावाट पन-बिजली का भी उत्पादन हो सकेगा। इससे वैसे पठारी इलाके में सिंचाई होगी, जहां पीने का भी पानी नही है। गरीबी-भूखमरी के कारण पूरा इलाका उग्रवाद से भयंकर रूप से ग्रसित है।

वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसके डैम (कुटकु डैम) में लोहे का गेट लगाकर जल का भंडारण करना है जिससे सिंचाई की स्थाई व्यवस्था हो सके। परन्तु वन विभाग झारखंड द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का हवाला देते हुए इस कार्य पररोक लगा दी गई है। बिहार के बंटवारे के बाद यह योजना दो राज्यों की हो गई है, जिसका डैम, बराज और मुख्य नहर का कुछ भाग झारखंड में ओर मुख्य नहर एवं अधिकांश वितरणियां बिहार में है। वर्तमान में दोनों ही राज्य सरकारें इस महत्वपूर्ण सिंचाई योजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु इच्छुक है। लेकिन आपत्ति के कारण विवश है। इस योजना के पूर्ण होने से लगभग 2000 करोड़ रुपए के खरीफ और रबी फसलों का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा।

मेरी सरकार से मांग होगी कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने कुटकु डैम में लोहे का फाटक लगाने पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, उसे हटाया जाए जिससे दो राज्यों के लगभग 5 लाख परिवार किसान और खेतिहर मजदूर जो मूलतः कृषि पर निर्भर है, का जीवन यापन सुगम हो सके।